Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies
ISSN: 3107-5088, Vol. 2, Issue-3 (July-Sep, 2026), pp.19-24, www.cognitivethinking.in

भारत की नई आर्थिक सुरक्षा रणनीति : आत्मनिर्भरता और विविधीकरण

1. **डा0 राहुल कुमार**, असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग, एस0 एस0 वी0 कालेज, हापुड़
2. **डा0 गजेन्द्र सिंह**

D.O.I. https://doi.org/10.5281/zenodo.21398262
Article: Received: 20/06/2026, Returned: 30/06/2026, Accepted:14/07/2026, Published:15/07/2026.
@ 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

संक्षेप– कोविड–19 महामारी के दोरान भारत और चीन के बीच 2020 में हिमालयी सीमा पर गलवान घाटी में हुए घातक संघर्षों ने चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न संप्रभुता के मुद्दों को रेखांकित किया है। ये निर्भरताएं तीन प्रमुख क्षेत्रों में दिखाई देती हैं व्यापारिक, तकनीकी और वित्तीय। भारत औद्योगिक वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए चीनी आयात पर निर्भर है, जो उसकी घरेलू कंपनियों के विकास को सीमित करता है और उसके व्यापार घाटे को बढ़ाता है, इसके अतिरिक्त, देश ऊर्जा, दूरसंचार और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी तकनीकों पर निर्भर है, जिससे महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएं पैदा होती हैं। कुछ चीनी निवेशों, विशेष रूप से भारतीय डिजिटल स्टार्ट–अप को अब रणनीतिक कमजोरियों के रूप में देखा जाता है। गलवान घटना के जवाब में, भारत ने इन कमजोरियों को कम करने के उद्देश्य से कई उपाय पेश किए, जिनमें सीमावर्ती निवेशों पर प्रतिबंध और सरकारी अनुबंधों से चीनी कंपनियों को बाहर करना शामिल है, इसके साथ ही भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों की शुरुआत की इस प्राकर भारत ने अपने प्रतिद्वंदी चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपने आर्थिक समझौतों को मजबूत करने और उनमें विविधता लाने के लिए भी काम किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ कई मुक्त–व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि क्वाड देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ–साथ फ्रांस, ताइवान, इजराइल और यूरोपीय संघ के साथ तकनीकी सहयोग को तेज किया है।

मुख्य शब्दः दीर्घकालिक, नवाचार, चिंतन, आकांक्षा, अत्याधुनिक, अल्पावधि, संरेखण

प्रस्तावना– 23 अक्टूबर, 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पिछले पांच वर्षों में अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक ने दोनों एशियाई महाशक्तियों के बीच संबंधों में सुधार की शुरुआत को चिह्नित किया, जोकि जून 2020 में गलवान घाटी में सीमा पर चीनी और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से काफी खराब हो गए थे। गलवान संघर्ष ने भारत–चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंधों में भारी गिरावट आयी जिसे चीन के प्रति भारत की कठोर आर्थिक नीतियों, भारत और चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते सैन्यीकरण, और सीमा वार्ता में आए गतिरोध के रूप में देखा गया। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दावा किया कि ''पूर्वी लद्दाख में चीनी, सैनिकों की वापसी अब पूरी तरह से पूरी हो चुकी है'' लेकिन चीन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों की वास्तविकता को लेकर संदेह अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि चीन 'एकतरफा कार्रवाई से स्थिति बदलने' की नीति का आदि रहा है। भी इस राजनयिक सुधार के पीछे के कारणों पर विचार करना जरूरी है। हालांकि राजनीतिक, सैन्य और भू–राजनीतिक कारक भी इस सुधार की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन चीनी वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और पूंजी पर भारत की भारी निर्भरता ने इस तालमेल की इच्छा में संभवतः एक निर्णायक भूमिका निभाई है।

चीन के आर्थिक प्रभाव को कम करना– गलवान घटना के बाद भारत सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसका उद्देश्य अल्पावधि में चीनी प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा करना जबकि दीर्घकालिक

ISSN: 3107-5088, Vol. 2, Issue-3 (July-Sep, 2026), pp.19-24, www.cognitivethinking.in

में देश की आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल की शुरुआत की गई। हालांकि, भारत के लिए अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना कठिन साबित हो रहा है।

रक्षात्मक आर्थिक उपायों को लागू करना– चीनी निवेश को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में 'पड़ोसी देशों' से होने वाले निवेश के नियमों को कड़ा कर दिया। इस संशोधन के बाद से चीनी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य हो गया है।1 इसके अलावा, जून 2020 से, चीनी डिजिटल ऐप्स पर लगातार कई चरणों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध इस तर्क पर लगाए गए कि इनमें से कुछ ऐप्स 'अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुरा सकते हैं और गुप्त रूप से भारत से बाहर स्थित सर्वरों पर भेज सकते हैं'। इस प्रकार 2020 और 2023 के बीच भारतीय बाजार से लगभग 550 चीनी एप्लिकेशन (टिकटॉक और वीचौट सहित) हटा दिए गए।2 16 दिसंबर, 2020 को एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी गई, जिसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क से केवल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक द्वारा नामित 'विश्वसनीय' उपकरणों को ही जोड़ने की आवश्यकता है। मई 2020 में, संचार मंत्रालय ने जेडटीई और हुआवेई को अपने भविष्य के 5जी नेटवर्क से बाहर कर दिया, और भारतीय नेटवर्क में पहले से मौजूद चीनी उपकरणों को बदलने के लिए चर्चा चल रही है।3 भारत सरकार ने चीनी स्मार्टफोन ब्रांडों (विवो, ओप्पो) पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उन पर महत्वपूर्ण दबाव भी डाला है।4 चीनी कंपनियों की भारतीय बाजार तक पहुंच को भी मध्य–2020 से सीमित कर दिया गया है। सार्वजनिक निविदाओं के लिए आवेदकों को अपने उत्पादों के मूल देश को निर्दिष्ट करना आवश्यक कर दिया गया था, जो कि वास्तव में सरकारी अनुबंधों से चीनी उत्पादों को बाहर करने के लिए उठाया गया एक सही कदम था। दिसंबर 2020 में, चीनी रेल कंपनी सीआरआरसी को 44 ट्रेनों के निर्माण के लिए 21.6 बिलियन डॉलर के टेंडर से अयोग्य घोषित कर दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव– इन्वेस्टमेंट कंट्रोल एक्ट (निवेश नियंत्रण अधिनियम) ने चीनी निवेश पर रोक लगा दी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 2019 में 4.8 बिलियन डॉलर से गिरकर 2020 में 100 मिलियन डॉलर रह गया, और फिर 2021 में गिरकर शून्य हो गया। इस बीच चीनी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े 2022 में भारतीय बाजार से चीनी निवेशकों की वापसी को दर्शाते हैं। टेक (तकनीक) क्षेत्र में, अलीबाबा और कुछ हद तक टेनसेंट ने 2020 से भारतीय स्टार्ट–अप में अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी है। हालांकि, चीनी निवेशकों के पीछे हटने से यह क्षेत्र वास्तव में प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य निवेशकों, मुख्य रूप से अमेरिकी और भारतीय, ने इस खाली जगह को जल्दी से भर दिया है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने ई–कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट में टेनसेंट के 77 प्रतिशत शेयर खरीद लिए। शेयर धारिता में यह बेहद आसान बदलाव दिखाता है कि हाल के वर्षों में भारतीय टेक क्षेत्र अधिक आकर्षक बन गया है। इसके अलावा, स्थानीय वेंचर कैपिटल बाजार भी तेजी से विकसित हो रहा है जिसके कारण प्रमुख क्षेत्रों (ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन) में कई निवेश परियोजनाएं निलंबित या छोड़ भी दी गईं। चीनी कंपनियां 2020 से भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत कर रही हैं। भारत में चीनी वाणिज्य मंडल के अनुसार, उनमें से कम से कम 500 कंपनियों की भारतीय वित्त मंत्रालय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच की गई है।5

2020 से रक्षात्मक उपायों के लागू होने से कुछ स्थानीय उद्योगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में बाधा आई है। एप्पल इसका एक सटीक उदाहरण है। आईफोन उत्पादन का एक हिस्सा चीन से भारत स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाला यह अमेरिकी समूह, जो अब अपने वैश्विक आईफोन उत्पादन का 14 प्रतिशत भारत में बनाता है, 2027 तक इस हिस्से को बढ़ाकर 25 करने का लक्ष्य रखता है। स्मार्टफोन उत्पादन के लिए एक उपयुक्त स्थानीय इकोसिस्टम की अनुपस्थिति में, एप्पल को अपने चीनी आपूर्तिकर्ताओं (युतो, लाईटेक, बीवाईडी इलेक्ट्रॉनिक्स, सुनवोडा) पर निर्भर रहना पड़ा है। लेकिन 2020 से लागू प्रतिबंधों, विशेष रूप से वीजा और चीनी निवेश पर, ने भारत में इन आपूर्तिकर्ताओं के आने में देरी की है, जिससे भारत में एप्पल का विस्तार धीमा हो गया है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, चीन के साथ सीमा विवाद के कारण 2020 और 2023 के बीच इस क्षेत्र के उत्पादन में लगभग 15 बिलियन डॉलर की कमी आई है, साथ ही 10000 नौकरियों का नुकसान हुआ है।6

ISSN: 3107-5088, Vol. 2, Issue-3 (July-Sep, 2026), pp.19-24, www.cognitivethinking.in

'आत्मनिर्भर भारत' नए संकटों के दौर में आत्मनिर्भरता की एक नई सोच– आर्थिक स्वायत्तता की अवधारणा भारतीय राजनीति के लिए नई नहीं है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, स्वदेशी आर्थिक आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के उत्पादों पर निर्भरता को कम करने को बढ़ावा दिया। इस अवधारणा का भारतीय आर्थिक और राजनीतिक विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, भारत द्वारा शुरू किया गया 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम आर्थिक खुलेपन और विदेशी निवेशकों के लिए स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसी तर्क का पालन करता है। यह कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन इसका विस्तार लगभग पंद्रह अन्य क्षेत्रों में भी है। इसके अलावा मार्च 2020 में सब्सिडी के माध्यम से रणनीतिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 'उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं' शुरू की गईं। शुरुआत में, चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर तीन क्षेत्रों को लक्षित किया गया था जैसे सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घटक और चिकित्सा उपकरण। 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा की शुरुआत का उद्देश्य भारत की स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करके उसे अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। जिसमें आर्थिक विकास को गति देना, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, व्यावसायिक माहौल में सुधार करना, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास करके भारत की मानवीय क्षमता का लाभ उठाना, और घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना है।7 इस पहल का बजट 260 बिलियन डॉलर है, जो स्वास्थ्य, कृषि, एमएसएमई सहायता, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। गलवान की घटनाओं के कुछ महीनों बाद, दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच घोषित नए क्षेत्रों में पीएलआई कार्यक्रम के विस्तार के साथ आत्मनिर्भर भारत पहल का दायरा बढ़ाया गया। ये नए क्षेत्र वे हैं जहां चीन पर निर्भरता सबसे मजबूत है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, खाद्य उत्पाद, ड्रोन, ऑटोमोबाइल, सौर पैनल, बैटरी, कपड़ा, घरेलू उपकरण और स्टील। चीनी कंपनियों को इन कार्यक्रमों से बाहर रखा गया है।

भारत का कठिन औद्योगीकरण– भारत, चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो 2021 और 2023 के बीच 12 बिलियन डॉलर और बढ़ गई। हालांकि, आनुपातिक संदर्भ में, भारत के कुल आयात में चीनी आयात की हिस्सेदारी घट रही है, जो 2020 में 16.5 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 15 प्रतिशत हो गई है। रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में चीनी कंपनियों की मजबूत उपस्थिति और कुछ आवश्यक उत्पादों के लिए स्थानीय विकल्पों की कमी के कारण चीन पर निर्भरता कम करने का काम जटिल हो गया है। हालांकि दस साल पहले 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से भारतीय निर्यात दोगुना हो गया है, 'मेक इन इंडिया' रणनीति उन क्षेत्रों में सबसे अधिक सफल रही है जो सार्वजनिक खरीद से निकटता से जुड़े हैं, जैसे कि रक्षा क्षेत्र, जहां विदेशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए तेजी से तकनीकी हस्तांतरण करना पड़ रहा है।8 वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपने खराब एकीकरण के अलावा, भारत की औद्योगिकीकरण की गति कई संरचनात्मक कारकों से बाधित है। इसके कार्यबल की कम गुणवत्ताय भारत में केवल 2.3 प्रतिशत कार्यबल ने ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 96 प्रतिशत और जापान में 80 प्रतिशत है।9 भारत, जिसके पास उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही सबसे अधिक आयात शुल्क थे, उसने 2016 और 2022 के बीच इन्हें 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

वैकल्पिक साझेदारों के साथ भारत के दायरे का विस्तार – चीनी प्रतिस्पधा का सामना करने के लिए भारत के पास साझेदारों का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसे उसने अपनी बहु–संरेखण की नीति के कारण समय के साथ विकसित किया है। ये साझेदार, जिन्हें हितों के आधार पर चुना गया है न कि भावनाओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और निवेश व तकनीकी विशेषज्ञता को आकर्षित करके अपने उद्योग का विकास करने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि, ये निवेश अभी भी इतने पर्याप्त नहीं हैं कि एक वास्तविक औद्योगिक प्रगति को संभव बना सकें।

आपूर्ति श्रंखला की सुदृढता इंडो–पैसिफिक सहयोग का एक नया स्तंभ – भारत कई पश्चिमी और एशियाई देशों के साथ चीनी सामानो पर अपनी निर्भरता कम करने की समान इच्छा साझा करता है। इसलिए आर्थिक सुरक्षा स्वाभाविक रूप से भारत और उसके पश्चिमी साझेदारों के बीच सहयोग का एक केंद्रीय मुद्दा बन गई है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 'क्वाड' और 'इंडो–पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क' आदर्श मंच हैं। अमेरिका की पहल पर 2022 में शुरू किए गए चौदह देशों को एक साथ लाने वाले एक विशाल आर्थिक समझौते के सदस्य देशों ने 'आपूर्ति श्रृंखला' के तहत

अपना पहला समझौता पूरा किया।10 मार्च 2023 के शिखर सम्मेलन में क्वाड सदस्यों (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत) ने अपने सहयोग का विस्तार ऊर्जा संक्रमण और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे कि सेमीकंडक्टर, एआई और नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियों तक किया है। इस सहयोग की एक प्रतीकात्मक परियोजना भारत में 3.3 गीगावाट के सौर पैनल कारखाने का निर्माण है, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में हुआ था और इसे अमेरिकी फंडिंग (वित्तीय सहायता) का समर्थन प्राप्त है। यह संयंत्र कैडमियम टेल्यूराइड से सौर पैनल बनाता है, जिसका अर्थ है कि यह सिलिकॉन के लिए चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर नहीं है।11 अपने साझेदारों के साथ हितों का यह मिलाप नए अवसर भी खोलता है, जिससे वह 'चाइना 1' योजना के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करके विनिर्माण केंद्र के रूप में खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो सके।

नई रणनीतिक साझेदारियों के केंद्र में मुख्य खनिज –भारत ने अपने क्वाड भागीदारों और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग को तेज किया है। उसने जून 2021 तक आठ 'पारस्परिक रूप से महत्वपूर्ण' संकटकालीन खनिजों की पहचान की है, जिनके लिए वह खुद को भारत के पसंदीदा आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना चाहता है। दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने 29 दिसंबर, 2022 को लागू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया से आने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर सभी सीमा शुल्कों को हटा दिया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली एक व्यापक पहल, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप में जून 2023 में भी शामिल हुआ, जो चौदह देशों को एक साथ लाती है। भारत सरकार ने विदेशों में खनिज संसाधनों विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों की पहचान करने और उन्हें अधिग्रहित करने के लिए 2019 में, एक समर्पित सार्वजनिक कंपनी, खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड का गठन किया।

नए व्यापार सहयोगी –गलवान 2020 की घटना के बाद भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता लाने के प्रयासों को तेज कर दिया। इसने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर अपने पारंपरिक रूप से सतर्क रुख में धीरे–धीरे ढील दी है, और मॉरीशस (2021), संयुक्त अरब अमीरात (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022) और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी समझौतों के मसौदों पर चर्चा चल रही है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ व्यापार चार वर्षों (2020–2024) में दोगुना हो गया है। इस अवधि के दौरान रूस के साथ व्यापार में भी काफी विस्तार हुआ, जो मुख्य रूप से रूसी तेल के बढ़ते भारतीय आयात के कारण 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया।

भारत के मुख्य आर्थिक साझेदारों के साथ बेहतर तकनीकी सहयोग – भारत अपने मुख्य साझेदारों के साथ अपने तकनीकी सहयोग को मजबूत कर रहा है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा के मोर्चे पर भारत अपने हथियारों के आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है ताकि रूस पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सके, जो लंबे समय से उसका मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा है (पिछले बीस वर्षों में भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत रही है), जबकि वह अभी भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बना हुआ है।12 फ्रांस अब रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, जिसे भारत की आपूर्तिकर्ता विविधीकरण नीति से काफी लाभ हुआ है। इन अनुबंधों में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थानीय उत्पादन की आवश्यकताएं तेजी से शामिल की जा रही हैं। मझागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड शिपयार्ड में असेंबल की गई अंतिम स्कॉर्पीन पनडुब्बी, 'नेवल ग्रुप' से महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तांतरण के साथ भारतीय रक्षा क्षमताओं के स्वदेशीकरण के लिए एक बड़ी सफलता का प्रतीक है। यह साझेदारी जुलाई 2023 में आईएनएस विक्रांत विमानवाहक पोत के लिए तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों और 26 राफेल–मरीन की खरीद की घोषणा के साथ जारी है। भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और रक्षा सहयोग, जो 2008 में नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से लगातार बढ़ा है, यह अमेरिकी विदेश नीति में 'फ्रेंडशोरिंग' मित्र देशों से व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा देने की अवधारणा के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सहयोगियों और भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।13

ताइवान और इजराइल धीरे–धीरे क्रमशः सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्रों में भारत के लिए प्रमुख वार्ताकार के रूप में स्थापित हो गए हैं। इजराइल मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, निगरानी और साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों सहित उच्च गुणवत्ता वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करता है। भारत इजराइल का प्रमुख हथियार ग्राहक है, जो 2019 और 2023 के बीच उसके हथियार निर्यात का 37 प्रतिशत हिस्सा था।14 2020 के दशक की शुरुआत से, भारत अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक, यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। 2022 में 'ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल' की शुरुआत उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके तहत कार्य के तीन क्षेत्र हैं– डिजिटल और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, हरित प्रौद्योगिकियां और व्यापार, निवेश व आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन। मई 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा के दौरान, जर्मनी ने भारत के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए 10 बिलियन यूरो देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

निष्कर्ष – दीर्घकालिक रूप में, चीन के सामने भारत की आर्थिक सुरक्षा रणनीति की सफलता उसके औद्योगिक विकास को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करेगी, जिसमें उपयुक्त कौशल की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा एक जटिल नियामक वातावरण कम अनुसंधान एवं विकास निवेश, मजबूत व्यापार संरक्षणवाद और लगातार बना रहने वाला भ्रष्टाचार भी शामिल हैं। लेकिन भारत के पास अपनी औद्योगिक और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने के लिए बड़ी संपत्तियां भी हैं। पहला भारत के पास युवा और प्रचुर मात्रा में कार्यबल है, जो 2050 तक बढ़ता ही रहेगा, दूसरा इसे साझेदारों के एक व्यापक और मजबूत नेटवर्क का लाभ मिलता है जो इसकी विकास पहलों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं भारत अब चीन की तुलना में अमेरिका में अधिक निवेश करता है और उन्होंने दावा किया कि 'मेक इन इंडिया' और 'मेड इन अमेरिका' पहलें एक–दूसरे की पूरक हैं।36 भारत को अमेरिका की ओर से अमेरिकी रुख के साथ अधिक निकटता से संरेखित होने के दबाव का भी डर है, जिससे चीन के साथ उसके पहले से ही जटिल संबंध और कठिन हो सकते हैं।

चीन–भारत संबंध उन दो देशों के बीच मजबूत, अत्यधिक विषम आर्थिक निर्भरता के दुर्लभ उदाहरणों में से एक हैं जिनके राजनीतिक संबंध गहरे विरोध से चिह्नित हैं। भारत एक नाजुक स्थिति में है जो चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण जनभावना और एलएसी पर महत्वपूर्ण चीनी सैन्य दबाव के बीच फंसा है, जबकि साथ ही इसे आर्थिक मोर्चे पर व्यावहारिकता और यथार्थवाद का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चूंकि भारत और चीन एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य कार्यप्रणाली खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

संदर्भ–

1. जे शेरमन, ''द प्रोबलम विद इण्डियाज ऐप बेन्स'' एटलांटिक काउन्सिल, 27, मार्च 2023
2. मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन प्रेस रिलीज, 29 जून 2020 https://pib.gov.in.
3. डी डी क्रूज, '' चाईनाज स्मार्टफोन कम्पनीज अण्डर सिक्रूटनी इन इण्डियाः ओप्पो, वीवो टू मेक बिग चेनजिज फॉर कम्पलाइंस,'' बिजनिश टूडे, 11 मार्च 2024 www.businesstoday.in.
4. ए, सिंह, '' टू स्टे और टू गोः डीकोडिंग चाईनीज एन्टरप्राइस इण्डिया डेलेमा,'' ऑबजर्व रिसर्च फाउन्डेशन, मई 2024
5. एस. श्रीवास्तव, '' इण्डिया वान्टस टू गिव चाईनीज विसास क्विक्ली टू हैल्प इट्रस आउन बिजनिश,'' द इकोनोमिक टाइम्स, 17 जुलाई, 2024 https://economictimes.indiatimes.com.
6. प्राइम मिनिसटर मोदीज स्पीच टू द नेशन ऑ 12 मई 2020 www.pmindia.gov.in.
7. ''नेशनल स्किल डवलेपमेन्ट मिशनः ए फ्रेमवर्क फॉर इम्पलीमेंटेशन,'' गर्वनमेंट ऑफ इण्या, 15 जुलाई 2015 https://msde.gov.in.
8. इन्डो–पेसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवक फॉर प्रोसपेरिटी एग्रीमेंट ऑन सप्लाई चेन रेजिलाईंस, साइन्ड 13 नवम्बर 2023 www.mofa.go.jp.
9. यू. एस. इण्टरनेशनल डवलपमेंट फाईनेंस कॉपरेशन प्रेस रिलीज, 11 जनवरी 2024, www.dfc.gov.in

10. ''इण्डियाज फाउसटेन पेक्ट विद रसिया इज स्ट्रेंदिंग,'' द इकोनोमिस्ट, 13 जनवरी 2025 www.economist.com.
11. टी. गोमर्ट एण्ड एस. जेन, ''इम्पोसिबल डिक्पलिंग, इम्प्रोबेबल कॉपरेशनः इकोनोमिक इण्टरडिपेंडेंसीज इन द फेस ऑफ पॉवर रिवेलरीज,'' आई एफ आर आई स्टडीज, इफरी,2 नवम्बर 2023
12. पी. वेजेमन, एण्ड के. डिजोकिक एट अल,''ट्रेंडस इन इण्टरनेशनल आर्म्स ट्रॉसफरर्स, स्टाकहोम इण्टरनेशनल पीस रिर्सच इन्सटीटयूट, 2023 पेज 2
13. ''इकोनोमिक सर्वे 2023–2024'', मिनिस्ट्री ऑफ फाईनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स, जुलाई 2024
14. ''नो रिव्यू ऑफ पोलिसी ऑन चाईनीज एफ डी आईः गोयल,'' फाईनेंशियल एक्सप्रेस, 31 जुलाई 2024 www.financialexpress.com.

Declaration by Author (s): "I/We hereby declare that this manuscript is my/our original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy." डा0 राहुल कुमार और डा0 गजेन्द्र सिंह